New Guidelines to Central Universities

695. DR. A. R. KIDWAI :†

DR. T. SUBBARAMI REDDY :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Ministry's proposal to subject foreign scholars and students visiting India to intense Government scrutiny has started;

(b) whether guidelines were issued to all Central Universities, directing them to take permission from Ministry for "all forms of foreign collaborations and other international academic exchange activities" taking place in India;

(c) if so, the details of new guidelines;

(d) whether Ministry has now full control not only over foreign exchange programmes but also over selection and monitoring procedure for foreign scholars/students coming to India for any form of academic activity; and

(e) if so, to what extent these guidelines are being strictly followed?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI) : (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) Guidelines have been issued by the Cabinet Secretariat in December 1999 regarding clearance for study/research schemes involving foreigners/foreign collaboration from security/sensitivity angle and by the Ministry of Home Affairs in September 2000 regarding security clearance for holding international conferences/seminars/workshop etc. in India. The guidelines which have been issued by Ministry of Human Resource Development on 31st January 2003 relate to the procedure to be observed by Central Universities to enter into an MoU with foreign Universities/Institutes with prior clearance from Ministry of Human Resource Development. Similarly, guidelines have been issued to State Universities and Deemed Universities permitting them to enter into MoU with foreign Universities/Institutes with prior clearance from State Governments and University Grants Commission respectively.

The guidelines do not intend to exercise control over either selection of foreign scholars/students coming to India or their academic activities. The guidelines lay down the procedure for obtaining approval of competent authority keeping security/sensitivity angle in mind.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. A. R. Kidwai.

DR. A. R. KIDWAI : Sir, I would like to know from the hon. Minister as to why it has become necessary to curtail academic freedom in research activities. Is it confined to the foreigners, foreign scholars and students coming to India because the guidelines say, 'academic collaboration and exchange programme'? You see, as regards foreign scholars, they come on the basis of valid visas granted to them after necessary enquiries. Then, what is the necessity of raising objections ?

Secondly, as far as academic collaboration is concerned, the hon. Minister, who himself is an eminent scientist, knows that knowledge is universal. The subjects on which research is going on in India is also going on in other countries. The scientists who are engaged in those subjects exchange ideas, research, collaborate and publish joint papers. Now academic matters have to be referred to the Ministry. Can we not trust the Vice-Chancellors, the Heads of the Departments and University scholars to see that research is in the right academic sphere ? Where is the question of security involved ? Has the hon. Minister come across any cases of insecurity in the field of academic research ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, प्रश्नकर्ता स्वयं प्रख्यात वैज्ञानिक रहे हैं और इस बारे में उनकी चिन्ता महत्वपूर्ण है। प्रश्न किसी प्रकार से भी शैक्षिक स्वायत्तता या शैक्षिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का नहीं है। देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर गृह मंत्रालय ने और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं और वे गाइडलाइंस सरकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज के समय में हमें यह देखना पड़ेगा कि जो भी विदेशी यहां पर अनुसंधान करने के लिए आते हैं, क्या वे किसी सेंसिटिव क्षेत्र में जाना चाहते हैं या हमारे आंकड़ों का वे कैसा उपयोग या दुरुपयोग करना चाहते हैं। जेनेटिक क्षेत्र में जो रिसर्च है, बायो-डाइवर्सिटी के क्षेत्र में जो रिसर्च है, उससे देश को जो नुकसान होने की संभावना रहती है, अगर उसमें हम थोड़ी सी भी असावधानी बरतें तो हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ विदेशी स्कालर्स के हमने बहुत से ऐसे रिसर्च देखे हैं जो हमारे देश की मौजूदा परिस्थिति में सांप्रदायिक तनाव या हमारे देश की जो अन्य समस्याएं हैं, उनको बढ़ाने वाले होते हैं। कोई ऐसी बात न होने पाए, कम्युनल दृष्टि से हमारे यहां कोई उत्पात न होने पाए, किसी सेंसिटिव क्षेत्र में वे न जाने पाएं, हमारे आंकड़ों का कोई दुरुपयोग न करने पाएं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर कुछ गाइडलाइंस दी गईं और उनको सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए वे गाइडलाइंस दी गई हैं। आज के समय में रिसर्च का चोरी किया जाना भी संभव हो गया है। जिस प्रकार की आजकल कनेक्टिविटीज हैं, सारी चीजें हैं, उनके कारण इस पर ध्यान देना पड़ता है। अब intellactual property rights हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा एक घटना हमारे ध्यान में आई थी कि बिना प्रोजेक्ट एप्रूव

किए हुए यहां कुछ विदेशी वैज्ञानिक आए, उन्होंने यहां 2-3 साल तक काम किया और चले गए। न तो उनके बारे में विभाग को पता था, न सरकार को पता था। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह घटना तो हमारे ध्यान में आ गई है, ऐसी और भी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि जो भी ऐसे अनुबंध हों, जहां भी ज्वाइंट रिसर्च हो.....

श्री सभापति : 5 मिनट बचे हैं मेरे पास।

डा. मुरली मनोहर जोशी : लेकिन उनका प्रश्न देश की सुरक्षा और एकेडेमिक स्वतंत्रता से संबंधित है। जहां भी ज्वाइंट रिसर्च का मामला हो, वहां हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। उस दृष्टि से केवल नोडल मिनिस्ट्री के सामने वह प्रपोजल ले जाकर, इन बातों पर ठीक से ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया है, यह देखा जाता है, इसका ही उसके अंदर प्रबंध है, और कोई प्रबंध नहीं है।

डा. ए. आर. किदवई : मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या दुनिया के दूसरे किसी मुल्क में भी ऐसी पाबंदी लगाई गई है एकेडेमिक रिसर्च पर ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : देखिए, पाबंदी लगाने के कई तरीके होते हैं और ये पाबंदियां विभिन्न तरीकों से लगती हैं लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, देखना यह चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है ?

श्री सभापति : डा. कर्णसिंह, आप पूछिए।

DR. T. SUBBARAMI REDDY : No, No, Sir . . . *(Interruptions)* . . . I have to put my supplementary. . . *(Interruptions)*

श्री सभापति : आपके सवाल पूछने पर सबको आपत्ति हो रही है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY : I have a news item which carries a beautiful picture of Dr. Murli Manohar Joshi. . . . *(Interruptions)* . . . Its title is, "New Foreign Policy spells curtains for academic research". . . . *(Interruptions)* . . . It has a very beautiful photograph of my friend Dr. Joshiji. . . . *(Interruptions)* . . .

श्री सभापति : क्या आप यह मानते हैं कि ये हैंडसम नहीं हैं ?

DR. T. SUBBARAMI REDDY : This picture is like a picture of a film star. . . *(Interruptions)* . . . It is a very handsome picture. . . *(Interruptions)*. . . I would like to know from the hon. Minister . . . . *(Interruptions)* . .

श्री सभापति : यह आदत है इनकी कि ये सब लोगों की फोटो इकट्ठा करते रहते हैं।

SHRI PREM CHAND GUPTA : Dr. Subbarami Reddy has said that Dr. Murli Manohar Joshi is very handsome. . . . *(Interruptions)* . . . Can you confirm that he would take him as a hero in his next film ? . . .

DR. T. SUBBARAMI REDDY : It says, "The Human Resource Development Minister's proposal to subject foreign scholars and students visiting India to intense Government scrutiny had picked up a storm a few months back. New

guidelines, for the first time, give the HRD Ministry full control not only over the foreign exchange programmes but also over the selection of monitoring procedure for foreign scholars." It has happened for the first time in the history. So, I would like to know from the hon. Minister what is the secret in taking away all the powers, for the first time, in fifty years of India's independence.

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है वह सत्य से कुछ दूर है। 1986 में कुछ गाइड-लाइंस बनाई गई थीं और उसके बाद 1999 में गाइड-लाइंस बनीं। गाइड-लाइंस को दोबारा दोहराया गया है। हमने तो केवल उसके अंदर व्यवस्था की है कि ये गाइड-लाइंस हैं इन पर ध्यान दिया जाए इन गाइडलाइंस का कारण क्या है वह भी हमने उसमें बतला दिया है।

DR. KARAN SINGH : Mr. Chairman, Sir, as the Chancellor of one of the Central Universities—Jawaharlal Nehru University—I would like to ask the hon. Minister whether he is aware of the fact that these guidelines have caused a great deal of disquiet among the academic community. There is a feeling that in a democratic and open society like ours, these sort of restrictive guidelines, are not approved. Would the hon. Minister accept the suggestion that he should call a conference of the Vice-Chancellors of the Central Universities—this question is directly relating to the Central Universities—talk with them, find out whether they are also feeling these to be restrictive. If there is a consensus that these guidelines need to be amended, will he do the needful?

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, हमें अभी किसी कुलपति ने इस संबंध में कोई कठिनाई का पत्र नहीं भेजा है। अगर कोई कठिनाई आएगी तो उसको हम जरूर देखेंगे। हमारे पास पत्र नहीं भेजा गया है। और दूसरी बात यह है कि देश की सुरक्षा यह प्रथम है। दुनिया में ऐसी कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है जहां इतना आतंकवाद है और जितने इस प्रकार के खतरे हैं। तो डेमोक्रेसी हम जरूर बचाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी इस देश में बची रहे इसलिए हम देश को हर प्रकार के खतरों से बचाना चाहते हैं। उसी की दृष्टि से हम प्रबंध कर रहे हैं।

*696. [The questioner (Shri Sukhbir Singh) was absent. For answer *vide* page 51-52 *infra*]

Review of food laws affecting growth of FPIs

*697. SHRI R.P. GOENKA : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a comprehensive review of various food laws administered by different Ministries has been undertaken recently to remove bottlenecks affecting growth of the food processing industries;

(b) If so, the details thereof; and